



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

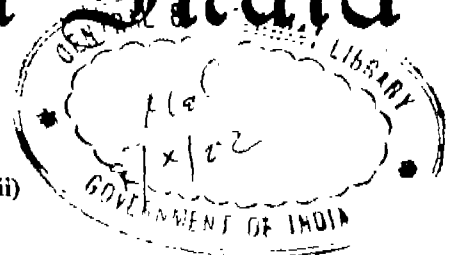
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 457]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 20, 2002/वैशाख 30, 1924

No. 457]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 20, 2002/VAISAKHA 30, 1924

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुख्य, 20 मई, 2002

का.आ. 535(अ).—यतः माननीय वित्त मंत्री ने 13 मार्च 2001 को संसद में घोषणा की थी, कि "स्टाक एक्सचेंजों का निगमीकरण जिसके द्वारा स्वामित्व, प्रबंधन, और व्यापारिक सदस्यता को एक दूसरे से अलग रखा जायेगा। प्रशासनिक कदम उठाये जायेंगे और तदनुसार, विधायी परिवर्तन, यदि अपेक्षित हो, प्रस्तावित किये जायेंगे।" उपर्युक्त नीति घोषणा के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इसमें इसके पश्चात् "भाप्रविबो" के रूप में निर्दिष्ट) ने समय समय पर स्टॉक एक्सचेंजों के साथ अपरस्पर्ीकरण के मुद्दे पर चर्चा की थी और

यतः भाप्रविबो बोर्ड ने 28 दिसंबर 2001 को आयोजित इसकी बैठक में स्टॉक एक्सचेंजों के अपरस्पर्ीकरण के मुद्दे पर चर्चा की और विनिश्चय किया कि अब से कोई सदस्य दलाल एक्सचेंज का पदाधिकारी नहीं होगा जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष इत्यादि का पद धारण करना है और एक्सचेंजों के निगमीकरण और अपरस्पर्ीकरण के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के अन्य प्रशासनिक और विधिक तौर-तरीके निर्धारित किये जा रहे हैं; और

यतः तत्पश्चात् भाप्रविबो ने परिपत्र सं. एसएमडी/पॉलिसी/सीआइआर-2/2002 तारीख 10 जनवरी, 2002 द्वारा, व उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज असोसिएशन लि (इसमें इसके पश्चात् "उप्रस्टाए" के रूप में निर्दिष्ट) को सम्मिलित करते हुए सभी एक्सचेंजों को कथित आदेश की तारीख से दो मास के भीतर, उनके नियम, संगम अनुच्छेद इत्यादि को उपयुक्त रूप से संशोधित करते हुए भाप्रविबो बोर्ड विनिश्चय कार्यान्वित करने का निदेश दिया; और

यतः भाप्रविबो ने पत्र सं. एसएमडी/यूपीएसई/4508/2002 दिनांक 19 मार्च 2002 द्वारा उप्रस्टाए को पुष्टि करने की सलाह दी कि क्या उन्होंने भाप्रविबो परिपत्र सं. 2 द्वारा जारी 10 जनवरी 2002 के

भाप्रविबो निदेश का अनुपालन किया था, जिसके द्वारा निदेश की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर कोई भी सदस्य दलाल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने के लिए अनुज्ञात नहीं था और उप्रस्ताए को यह पुष्टि करने की भी सलाह दी गयी कि उन्होंने भाप्रविबो बोर्ड द्वारा लिये गये उपर्युक्त विनिश्चय को और इस संबंध में सरकार के नीति विनिश्चय को प्रभावी करने के लिए नियम, संगम अनुच्छेद इत्यादि को उपयुक्त रूप से संशोधित किया था या नहीं; और

यतः ऊपर उल्लिखित पत्र और परिपत्र तारीख 10 जनवरी 2002 के उत्तर में, उप्रस्ताए ने इसके पत्र यूपीएसई/2001-02/7745 तारीख 19 मार्च 2002 द्वारा सूचित किया कि अभी भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का धारण स्टाक दलालों द्वारा किया जा रहा है यथा एक्सचेंज के संगम अनुच्छेद में उस तारीख तक संशोधन नहीं गया किया है; और

यतः नियम, संगम अनुच्छेद इत्यादि के संशोधन के विषय में, उपर्युक्त भाप्रविबो निदेश को प्रभावी करने के लिए, उप्रस्ताए के निदेशक बोर्ड ने 09 मार्च 2002 को एक असामान्य साधारण अधिवेशन बुलाया; और

यतः 09 मार्च 2002 को आयोजित असामान्य साधारण अधिवेशन में उपर्युक्त भाप्रविबो निदेश को कार्यान्वित करने के प्रस्तावित संकल्प पर विचार किया गया, उप्रस्ताए ने इसके पत्र तारीख 18.3.2002 द्वारा सूचित किया कि सदस्यों ने अभिकथित किया कि बैठक बुलाने की सूचना और इसका संकल्प उपर्युक्त नहीं है, कि शासी बोर्ड सूचना और प्रस्तावित संकल्प के लिए विधिमान्य कारण देने में असफल रहा था और सदस्यों ने कई प्रश्न किये जिनका उत्तर शासी बोर्ड ने नहीं दिया और बैठक के अध्यक्ष श्री एच के गर्ग ने कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार असामान्य बैठक को 06 अप्रैल 2002 तक स्थगित किया और

यतः यह नोट किया गया कि शासी बोर्ड स्पष्टीकरण देने में असफल रहा था कि प्रस्तावित संकल्प एक्सचेंज के हित में हैं या नहीं, कि शासी बोर्ड अपरस्पीकरण और निगमीकरण पर केंद्रीय सरकार की नीति को उचित तौर से स्पष्ट करने में समर्थ नहीं था, कि सदस्यों ने प्रश्न किया कि चूंकि एक्सचेंज का कॉर्पस उनके द्वारा अभिदत्त है, एक्सचेंज की निधि और संपत्ति का प्रबंधन उनके द्वारा किया जाना चाहिए, परंतु शासी बोर्ड अपरस्पीकरण और निगमीकरण पर केंद्र सरकार की नीति को उचित तौर से स्पष्ट करने प्रस्तावित संकल्प पारित करने की आवश्यकता के बारे में सदस्यों को विश्वास दिलाने में असफल रहा, कि शासी बोर्ड अधिवेशन के दौरान सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ नहीं था और यह उपदर्शित करता है कि एक्सचेंज का शासी बोर्ड नियम, संगम अनुच्छेद इत्यादि के संशोधन के लिए यथोचित कदम उठाने में असफल रहा, यहाँ तक कि भाप्रविबो द्वारा जारी उपर्युक्त निदेश में नियत कालावधि के अवसान के पश्चात् भी और उप्रस्ताए ने भाप्रविबो द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन नहीं किया और

यत्तः बोर्ड ने भाप्रविबो बोर्ड द्वारा किये गये विनिश्चय और इस संबंध में सरकार के नीति विनिश्चय को प्रभावी करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 4(3) के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अधीन इसके पत्र संदर्भ सं. एसएमडी/पॉलिसी/सीआइआर-2/2002 तारीख 10 जनवरी 2002 द्वारा एक आदेश जारी किया था, सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को इस आदेश की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर इसके नियम, संगम अनुच्छेद इत्यादि को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का निदेश देते हुए और आगे यह भी सूचित किया गया कि आदेश जारी होने की तारीख से दो मास के भीतर एक्सचेंज द्वारा उपर्युक्त आदेश का अनुपालन करने में असफल रहने पर, भाप्रविबो कथित धारा 8 के उपबंधों के अनुसार संबद्ध स्टॉक एक्सचेंजों के नियम बना सकेगा / नियम संशोधित कर सकेगा; और सदस्यों के प्रश्नों का समाधान करने में उप्रस्टाए के शासी बोर्ड की असफलता को देखते हुए और नियत कालावधि में उप्रस्टाए के संगम अनुच्छेद में संशोधन करने में और इसके द्वारा तारीख 10.1.2002 के आदेश के अनुपालन में उप्रस्टाए की असफलता को देखते हुए, भाप्रविबो उप्रस्टाए के अनुच्छेद 112 में संशोधनों को अधिसूचित करने के लिए मजबूर है और

यत्तः अधिकांश स्टॉक एक्सचेंजों ने 10.1.2002 के आदेश को प्रभावी करने के लिए उनके नियमों / संगम अनुच्छेदों में संशोधन किया है, और उप्रस्टाए अनुच्छेद 112 का संशोधन करने में असफल रहा है, उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए भाप्रविबो की राय है कि विनिधानकर्ताओं और पूँजी बाजार के हित में, लोक हित में भी, अनुच्छेद 112 को संशोधित करना आवश्यक और समीचीन है, इस आदेश में उपवर्णित रीति में, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कारणों के लिए, अर्थात् :

- (i) स्टॉक एक्सचेंजों के शीघ्र निगमीकरण के लिए जिसके द्वारा स्वामित्व, प्रबंधन, और व्यापारिक सदस्यता को स्टॉक बाजारों में संस्थागत प्रणालीतंत्र और व्यापार पद्धतियों को उन्नत करने के लिए एक दूसरे से अलग रखा जायेगा।
- (ii) इसके अलावा, बोर्ड देश के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के शासी बोर्ड की संरचना के संबंध में नियम, विनियम और उप-विधियों में एकरूपता बनाये रखने के लिए इसे वांछनीय पाता है।

अतः अब भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड कथित अधिनियम की धारा 29क के अधीन जारी इसकी अधिसूचना सं. का.आ. /573(अ) तारीख 3 जुलाई 1992 के अधीन भाप्रविबो द्वारा बोर्ड को प्रत्यायोजित शक्तियों के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप्रस्टाए के संगम अनुच्छेद के विद्यमान अनुच्छेद 112 को निम्नलिखित नये अनुच्छेद 112 द्वारा प्रतिस्थापित करता है:

112. i. वार्षिक साधारण अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् 10 दिनों के भीतर निदेशक बोर्ड के सदस्यों में से एक्सचेंज का अध्यक्ष निर्वाचित किया जायेगा।

- ii उपर्युक्त अनुसार नियुक्त अध्यक्ष एक वर्ष के लिए उसका पद धारण करेगा और पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

परंतु यह कि कोई सदस्य जिसने दो क्रमिक कालावधि के लिए अध्यक्ष का पद धारण किया है पुनः निर्वाचन के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने का पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा अंतिम बार ऐसा पद धारण करने के बाद से एक वर्ष की कालावधि व्यपगत न हो गयी हो।

परंतु यह कि एक्सचेंज का कोई दलाल सदस्य स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित नहीं होगा।

- iii वार्षिक साधारण अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् 10 दिनों के भीतर निदेशक बोर्ड के सदस्यों में से एक्सचेंज का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जायेगा।

- iv उपर्युक्त अनुसार नियुक्त उपाध्यक्ष एक वर्ष के लिए उसका पद धारण करेगा और पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

परंतु यह कि कोई सदस्य जिसने दो क्रमिक कालावधि के लिए उपाध्यक्ष पद धारण किया है पुनः निर्वाचन के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेगा जब तक कि उसके द्वारा अंतिम बार ऐसा पद धारण करने के बाद से एक वर्ष की कालावधि व्यपगत न हो गयी हो।

परंतु यह कि एक्सचेंज का कोई दलाल सदस्य स्टॉक एक्सचेंज का उपाध्यक्ष निर्वाचित नहीं होगा।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 20th May, 2002

S.O. 535(E).— the Hon'ble Finance Minister had announced in the Parliament on March 13, 2001, that "corporatisation of stock exchanges by which ownership, management, and trading membership would be segregated from each other. Administrative steps will be taken and legislative changes, if required, will be proposed accordingly." In accordance with the above, policy announcement, The Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as "SEBI") had discussed the issue of demutualisation with the stock exchanges from time to time and

Whereas SEBI Board in its meeting held on December 28, 2001, discussed the issue of demutualisation of the stock exchanges and decided that henceforth no broker member shall be an office bearer of an exchange that is hold the position of the President, Vice-President, Treasurer etc., and the other administrative and legal modalities for corporatisation and demutualisation of exchanges of the stock exchanges are being worked out; and

Whereas subsequently, SEBI directed all the exchanges including The Uttar Pradesh Stock Exchange Association Ltd (hereinafter referred to as "UPSE") vide circular no. SMD/POLICY/CIR-2/2002 dated January 10, 2002, to implement the SEBI Board decision by suitably amending their Rules, Articles of Association etc., within two months from the date of the said Order; and

Whereas SEBI advised UPSE vide letter no. SMD/UPSE/4508/2002 dated March 19, 2002 to confirm whether they had complied with the SEBI directive of January 10, 2002, issued vide SEBI Circular no. 2, whereby no broker member was allowed to hold office

as President, Vice-President within a period of two months from the date of the directive and UPSE was also advised to confirm whether they had suitably amended the Rules, Articles of Association etc., to give effect to the above decision taken by the SEBI Board and the policy decision of government in this regard; and

Whereas In response to the above mentioned letter and circular dated January 10, 2002, UPSE vide its letter no. UPSE/2001-02/7745 dated March 19, 2002 informed that the post of President and Vice-President are still being held by stock brokers as Articles of Association of the exchange has not been amended as on that date; and

Whereas as regards amendment to the Rules, Articles of Association etc., to give effect to the aforesaid SEBI directive, the Board of Directors of the UPSE convened an extra ordinary general meeting on March 09, 2002; and

Whereas the proposed resolution to implement the aforesaid SEBI directive was considered in the extraordinary general meeting held on March 09, 2002, UPSE vide its letter dated 18.3.2002 informed that the members alleged that the notice calling the meeting and its resolution are not proper, that the Governing Board had failed to give valid reasons for the notice and the proposed resolution and the members raised several queries which were not answered by the Governing Board and the Chairman of the meeting Shri H K Garg adjourned the extra ordinary meeting to April 06, 2002 as per the provisions of the Companies Act, 1956 and

Whereas, it is noted that that the governing board had failed to explain whether the proposed resolutions are in the interests of the exchange, that the governing board was not able to explain properly the policy of the central government on demutualisation and corporatisation, that the members raised the query that since the corpus of the exchange was contributed by them, the fund and property of the exchange should be managed by them, but the Governing Board failed to explain properly the policy of the central government on demutualisation and corporatisation convince the members on the necessity of passing the proposed resolution, that the governing board was not able to answer the queries of the members during the meeting and this indicates that the governing board of exchange failed to take adequate steps to amend the Rules, Articles of Association etc., even after the expiry of the stipulated time period in the aforesaid

direction issued by SEBI and the UPSE did not approve the amendments proposed by SEBI and

Whereas the Board had vide its letter Ref no. SMD/POLICY/CIR-2/2002 dated January 10, 2002 issued an Order under Section 8 of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 read with Section 4(3) of Securities and Exchange Board of India Act, 1992, directing all the recognised stock exchanges to suitably amend its Rules, Articles of Association etc., within a period of two months from the date of this Order to give effect to the decision taken by SEBI Board and the policy decision of Government in this regard and it was further informed that on failure by the exchange to comply with the above order within two months of the date of issue of the Order, SEBI may make the rules / amend the rules of the concerned stock exchanges in accordance with the provisions of the said Section 8; and in view of the failure of the Governing Board of UPSE to address the queries of the members and in view of the failure of UPSE to amend the articles of association of UPSE within the stipulated time and thereby comply with order dated 10.1.2002, SEBI is forced to notify amendments to article 112 of UPSE and

Whereas most of the stock exchanges have amended their rules/articles of association to give effect to the order of 10.1.2002, and there is failure of UPSE to amend article 112, in the light of the above SEBI is of the opinion that in the interests of the investors and the capital markets, as also in public interest, it is necessary and expedient to amend the Article 112, in the manner indicated in this Order, inter-alia for the following reasons namely:

- (i) To expedite the corporatisation of stock exchanges by which ownership, management, and trading membership would be segregated from each other to improve institutional mechanism and trading practices in the stock markets.
- (ii) Moreover, the Board finds it desirable to maintain uniformity in the Rules, Regulations and Bye-laws regarding composition of the Governing Board of various stock exchanges in the country.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Sub-section 2 of Section 8 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 read with the powers delegated to the Board by the SEBI under its notification no. S.O / 573(E) dated July 3, 1992 issued under Section 29A of the said Act, Securities and Exchange Board of India substitutes the

existing Article 112 of the Articles of Association of UPSE, by the following new Article 112:

112. i The president of the exchange shall be elected from amongst the members of the Board of Directors within 10 days after the conclusion of the annual general meeting.
- ii. The president appointed as above shall hold his office for one year and shall be eligible for re-election
Provided that no member who has held the office of the president for two consecutive terms shall be eligible to offer himself for re-election unless the period of one year has elapsed since he last held such office and ;
Provided that no broker member of the exchange shall be elected as President of the stock exchange.
- iii. The Vice President of the Exchange shall be elected from amongst the members of the Board of Directors within 10 days after the conclusion of the Annual General Meeting.
- iv. The Vice-President appointed as above shall hold his office for one year and shall be eligible for re-election;
Provided that no member who has held the office of the Vice-President for two consecutive terms shall offer himself for re-election unless a period of one year has elapsed since he last held such office and ;
Provided that no broker member of the exchange shall be elected the Vice President of the stock exchange.

[F. No. SEBI/LE/8579/2002]

G. N. BAJPAL, Chairman